



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 524 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 1995/भाद्र 17, 1917

No. 524]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1995/BHADRA 17, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1995

का० आ० 774 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 243ठ और अनुच्छेद 243 त्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अंडमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 186, लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 86, दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965 (1965 का 3) की धारा 46क, गोवा, दमन और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962 (1962 का 9) की धारा 45 क और अंडमान और निकोबार द्वीप नगर पालिका विनियम, 1994 (1994 का 5) की धारा 72 तथा गोवा, दमन और दीव नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 16) की धारा 143 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 324 (अ), अधिसूचना सं० का०आ० 325 (अ) अधिसूचना सं० का०आ० 326 (अ) अधिसूचना सं० का०आ० 327 (अ) सभी तारीख 23 अप्रैल, 1994 और अधिसूचना सं० का०आ० 386 (अ) तथा अधिसूचना सं० का०आ० 387 (अ), तारीख 23 मई, 1994 द्वारा यथा उपांतरित संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म के उपबंधों के अनुसरण में, अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्त आयोग गठित करते हैं जिसमें श्री वी० एस् जफा, अध्यक्ष और निम्नलिखित दो अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री आई० जी० झिंग्रान—सदस्य
2. श्री बी० एस् ऐलावादी—सदस्य

2. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. आयोग, निम्नलिखित विषयों की बाबत सिफारिशें करेगा :—

- (क) ऐसे करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों का अवधारण जो अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुद्दिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;
- (ख) भारत की संविधान विधि में से अंडमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान;

(ग) अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्यापय । उनके साधन आधार का विस्तार करने के लिए साधन और प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए उनकी क्षमता में उत्तरोत्तर सुधार का संवर्धन करने के लिए अपेक्षित अध्यापय ।

4. आयोग अपनी सिफारिशें करने में, अन्य बातों में, निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :—

- (क) प्रथमतः केवल यही उद्देश्य नहीं है कि अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप और उनकी पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखों में प्राप्तियों और व्यय का संतुलन हो, तत्पश्चात् वह रीति भी, जिससे पूंजी विनिधानों के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न हो;
- (ख) 31 मार्च, 1997 तक पूरी की जाने वाली योजना स्कीमों के संबंध में पूंजी आस्तियों और अनुरक्षण व्यय का अनुरक्षण और रख-रखाव तथा वे सन्निधिमूलक आधार पर विनिर्दिष्ट रकमों को पूंजी के अनुरक्षण के लिए सिफारिश की जाती है;
- (ग) वाणिज्यिक उपक्रमों, विद्युत् परियोजनाओं, पब्लिक सेक्टर उद्यमों, आदि में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा विनिधानों के संबंध में उचित प्रत्यागम सुनिश्चित करने की आवश्यकता;
- (घ) आयोग, विद्यमान साधनों पर आधारित पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व साधन का और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा, 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए, राष्ट्रीय वित्त आयोग की अवधि और 2000-2001 से 2009-2010 तक की अवधि के भी अनुरूप होने के लिए उद्गृहीत या विनियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों का निर्धारण करेगा । आयोग इस अवधि के लिए व्यय आवश्यकताओं और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले विकास के व्यापक क्षेत्रों का भी निर्धारण करेगा;
- (ङ) आयोग, अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप की दीर्घकालिक परिपेक्ष्य योजनाओं और विकासात्मक लक्ष्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित विनिधानों की पद्धति और अपेक्षित साधनों के लिए संभव स्रोतों पर भी विचार कर सकेगा;
- (च) आयोग, अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के संबंध में विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए 'समग्र निधि' के सृजन की साध्यता पर विचार कर सकेगा;
- (छ) व्यय में दक्षता और मितव्ययिता से संगत बेहतर राजवित्तीय प्रबंध के लिए गुंजाइश;
- (ज) आयोग, उपलब्ध किए गए वित्तीय परिष्वयों के लिए परियोजनाओं या स्कीमों (योजनागत और योजनेत्तर, दोनों और) के वस्तुगत प्रगति का मानीटर करने के लिए कोई पद्धति भी विकसित कर सकेगा ।

5. आयोग, पूर्वोक्त विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करने में, ऐसे सभी मामलों में अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों को, जहां जनसंख्या को पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने के लिए या करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों, आदि के निर्धारण के लिए कारक माना जाता है, अंगीकृत करेगा ।

6. आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर अपनी रिपोर्ट, 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि का समावेश करते हुए, अपने गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपलब्ध करा देगा । आयोग, उस आधार को, जिस पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, उपदर्शित करेगा और प्राप्तियों तथा व्यय के पंचायतवार और नगरपालिकावार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा ।

[फा सं यू-13034/26/95-ए.एन.एल.]

आर० आर० शाह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1995

**S.O. 774 (E).**—In pursuance of the provisions of the Article 243-I and 243-Y of the Constitution as modified by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos. S.O. 324(E), S.O. 325(E), S.O. 326(E), S.O. 327(E) all dated the 23rd April, 1994 and S.O. 386(E) and 387(E) dated the 23rd May, 1994, issued in exercise of the powers conferred by Article 243 L and 243 ZB of the Constitution and in exercise of the powers conferred by section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), section 86 of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994 (4 of 1994), Section 46A of the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965 (3 of 1965), Section 45 A of the Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation, 1962 (9 of 1962), and section 72 of the Andaman and Nicobar Islands Municipal Regulation 1994 (5 of 1994), and section 143 A of Goa, Daman and Diu Municipalities Act of 1968 (16 of 1968) the President is pleased to constitute a Finance Commission for the Union Territories of the Andaman

and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep consisting of Shri V.S. Jafa as the Chairman and the following two other members namely:—

1. Shri I. G. Jhingran, Member
2. Shri V. S. Ailawadi, Member

2. The Chairman and the other members of the Commission shall hold office for a period of one year from the date on which Chairman assumes his office.

3. The Commission shall make recommendations relating to the following matters :

- (a) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep;
- (b) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities of the Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep from the Consolidated Fund of India;
- (c) measures needed to improve the financial position of Panchayats and Municipalities in the Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep. Measures required to promote progressive improvement in their capacity to generate resources and incentives to enlarge their resource base.

4. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:

- (a) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep in the first instance and their Panchayats and Municipalities, thereafter in a manner that sufficient surplus is generated for capital investments;
- (b) the maintenance and upkeep of capital assets and maintenance expenditure on plan schemes to be completed by 31st March, 1997 and the norms on the basis of which specified amounts are recommended for the maintenance of the capital;
- (c) the need for ensuring reasonable returns on the investments by the Panchayats and Municipalities in commercial undertakings, power projects, public sector enterprises etc.,
- (d) the Commission shall assess the revenue resource of the Panchayats and Municipalities based on the existing resources and taxes, duties, tolls and fees proposed to be levied or appropriated by the Panchayats and Municipalities for the period 1997-98 to 1999-2000, to coincide with the period of the National Finance Commission and also for the period 2000-2001 to 2009-2010. The Commission shall, also, assess the expenditure needs for this period and the broad areas of development to be undertaken by the Panchayats and Municipalities;
- (e) the Commission may also consider the long term perspective plans and developmental goals of the Andaman & Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, the order of investments required to achieve these goals and the possible sources for the required resources;
- (f) the Commission may consider the feasibility of creation of a "Corpus of Funds" for developmental needs in respect of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep;
- (g) the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure;
- (h) the Commission may also evolve a system for monitoring physical progress of projects or schemes (on both plan and non-plan sides) against financial outlays made available.

5. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the latest population figures in all cases where population is regarded as a factor for providing grants-in-aid or for the assessment of taxes, duties, tolls, fees etc. to the Panchayats and Municipalities.

6. The Commission shall make its report available within a period of one year, from the date of its constitution, on each of the matters aforesaid, covering the period of three years commencing on the 1st day of April 1997. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the Panchayat-wise and Municipality-wise estimates of receipts and expenditure.

[F. No. U-13034/26/95-ANL]

R. R. SHAH, Jt. Secy.

